भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3463
सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

तेलंगाना में राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना

3463. श्री इटेला राजेंदर:
श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रोजगार सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए वर्ष 2015-16 में रोजगार कार्यालयों को मॉडल करियर केंद्रों (एमसीसी) के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा योजना आरंभ की थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तेलंगाना सहित जिला-वार कितनी निधि स्वीकृत और खर्च की गई है;

(ग) क्या तेलंगाना राज्य को 100 प्रतिशत सहायता अनुदान निधि के साथ 12 मॉडल कैरियर केंद्र स्वीकृत किए गए थे और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने तेलंगाना में राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना के अंतर्गत रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए नवनिर्मित 16 जिलों हेतु प्रथम चरण में 2,22,00,000/- रुपये और द्वितीय चरण में 1,28,00,000/-रुपये अर्थात कुल 3,50,00,000/- रुपये की राशि स्वीकृत की थी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त राज्य ने 2,22,00,000/- रुपये की पूरी राशि के प्रथम चरण हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र फॉर्म जीएफआर- 12सी में प्रस्तुत किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या 33 जिलों की निधि के संकलन के दौरान यह पाया गया कि राशि की गणना गलत तरीके से की गई थी और वास्तविक किया गया व्यय केवल 1,60,57,804/- रुपये है तथा खर्च नहीं की गई शेष राशि 61,42,196/- रुपये है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): सरकार, रोजगार कार्यालयों के एक नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार सेवा का कार्यान्वयन कर रही है। रोजगार केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों का संयुक्त विषय है। केंद्र रोजगार कार्यालयों के संचालन के लिए नीतियाँ, मानक और प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है, जबकि रोजगार कार्यालयों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधीन होता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

एनसीएस परियोजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में रोजगार कार्यालयों के उन्नयन के माध्यम से मॉडल कैरियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है ताकि आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से रोजगार चाहने वालों और नियोक्ताओं को राज्य और अन्य संस्थानों के सहयोग से ऑनलाइन/ऑफलाइन रोजगार मेलों का आयोजन करने, नियोक्ताओं को जुटाने, स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कैरियर परामर्श प्रदान करने आदि जैसी कैरियर संबंधी सेवाएं प्रदान की जा सकें। अब तक, तेलंगाना राज्य में 12 एमसीसी अनुमोदित किए गए हैं।

अब तक, मंत्रालय ने मॉडल करियर केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 9014.86 लाख रुपये जारी किए हैं, जिनमें से 396.57 लाख रुपये तेलंगाना को जारी किए गए हैं। इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने 6646.80 लाख रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किए हैं और 901.99 लाख रुपये की राशि भारत की संचित निधि (सीएफआई) में वापस भेज दी गई है। तेलंगाना राज्य ने 342.78 लाख रुपये की यूसी जमा की है और राज्य द्वारा 53.73 लाख रुपये की राशि सीएफआई को वापस जमा की गई।

इसके अलावा, बुनियादी आईटी ढांचे के निर्माण, मामूली नवीनीकरण और जिला स्तरीय रोजगार मेलों के आयोजन के लिए एनसीएस योजना के रोजगार कार्यालयों को जोड़ने के घटक के तहत तेलंगाना राज्य को 350.00 लाख रुपये की राशि भी जारी की गई थी। राज्य सरकार ने 160.57 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया है और 189.43 लाख रुपये की अव्ययित शेष राशि को सीएफआई में वापस जमा कर दिया है। तथापि, एनसीएस योजना के रोजगार कार्यालय घटक को आपस में जोड़ने का कार्य 15वें वित्त आयोग चक्र में जारी नहीं रखा गया था।

*****